बजट 2021–22 की मुख्य विशेषताएं

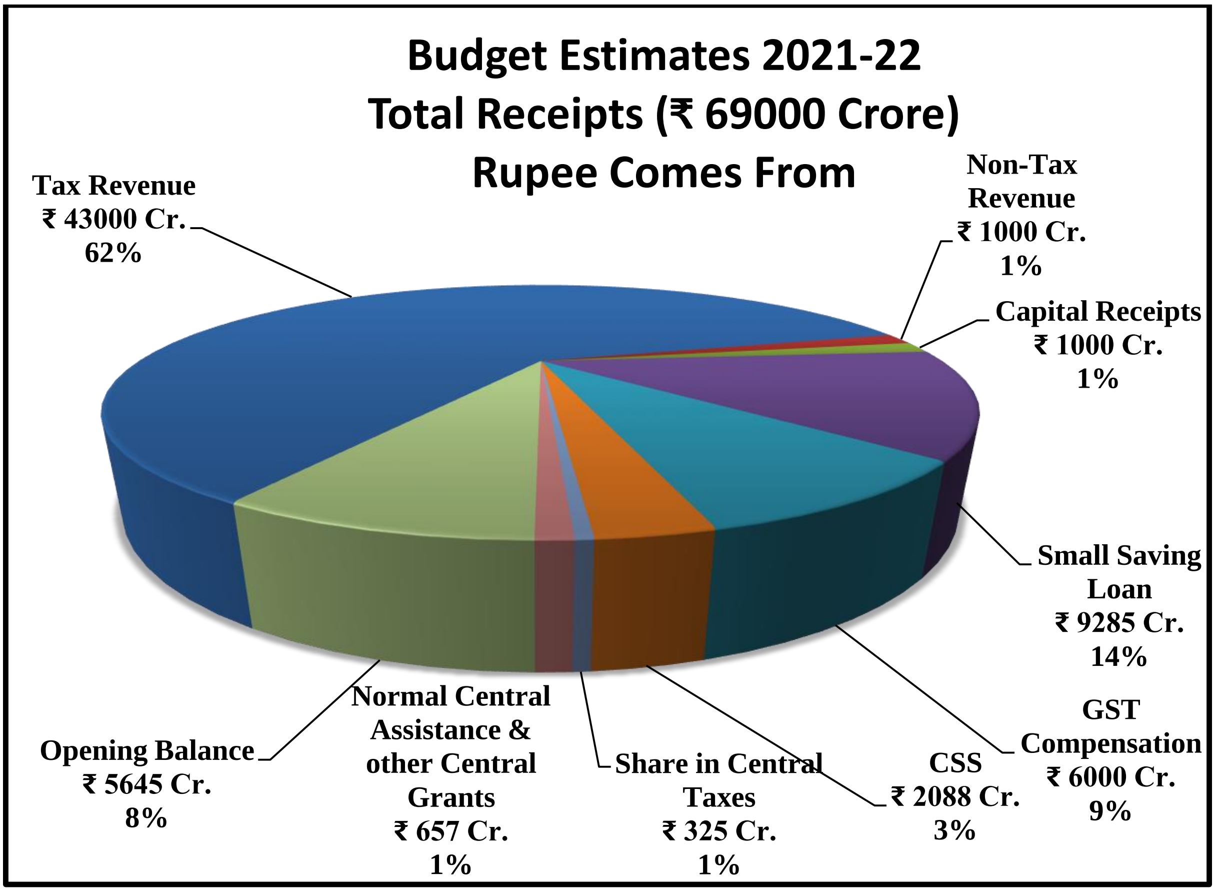

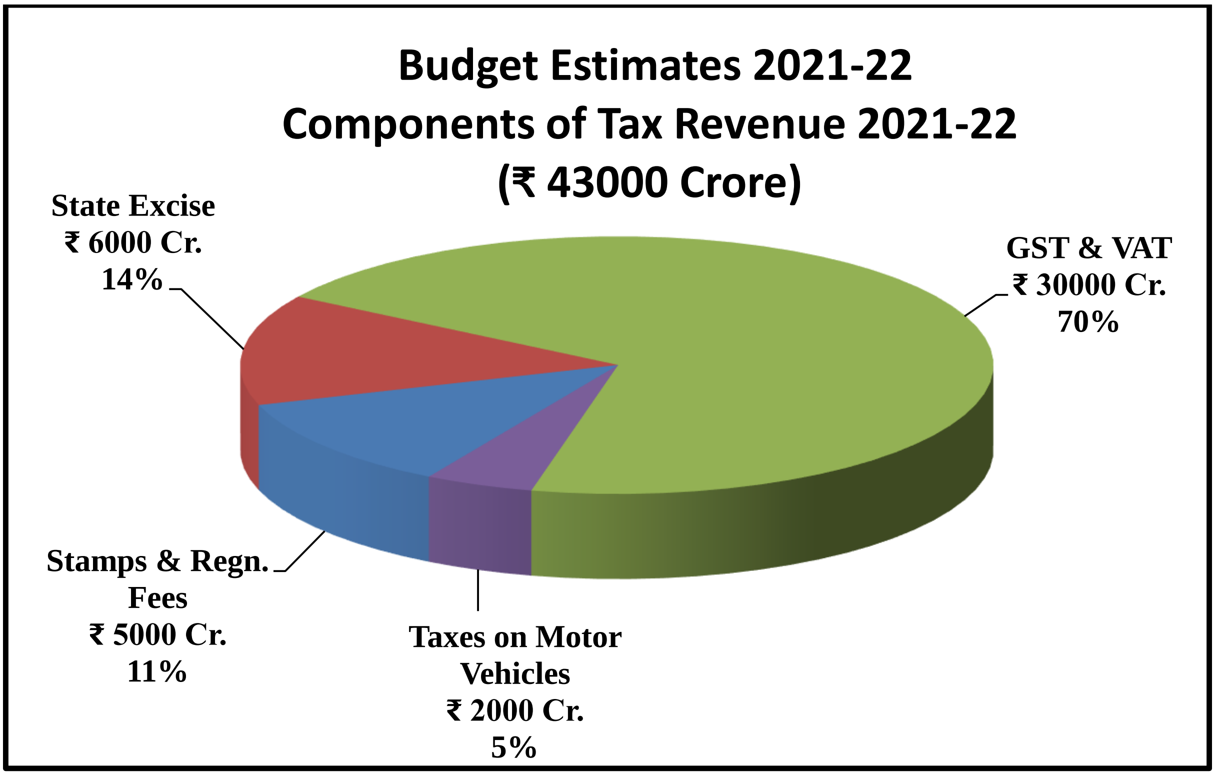

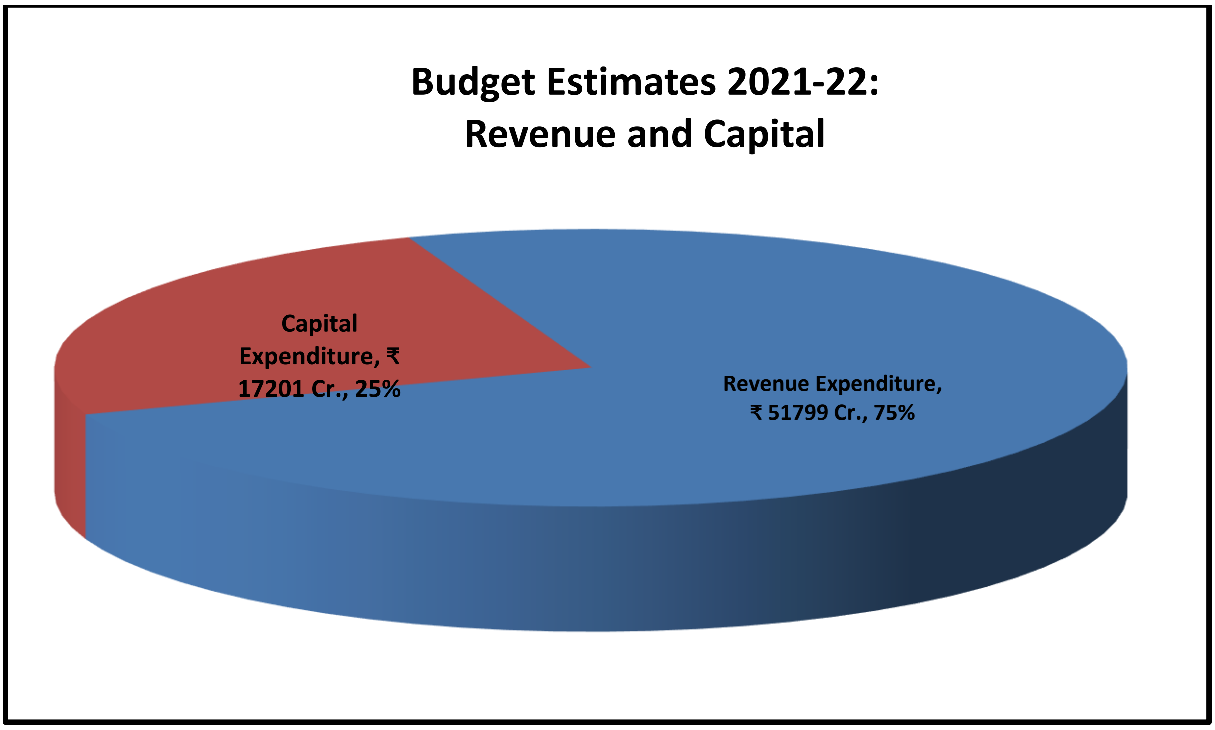
Budget Estimates 2021-22:
Revenue and Capital
Capital Expenditure, ₹ 17201 Cr., 25%
Revenue Expenditure, ₹ 51799 Cr., 75%

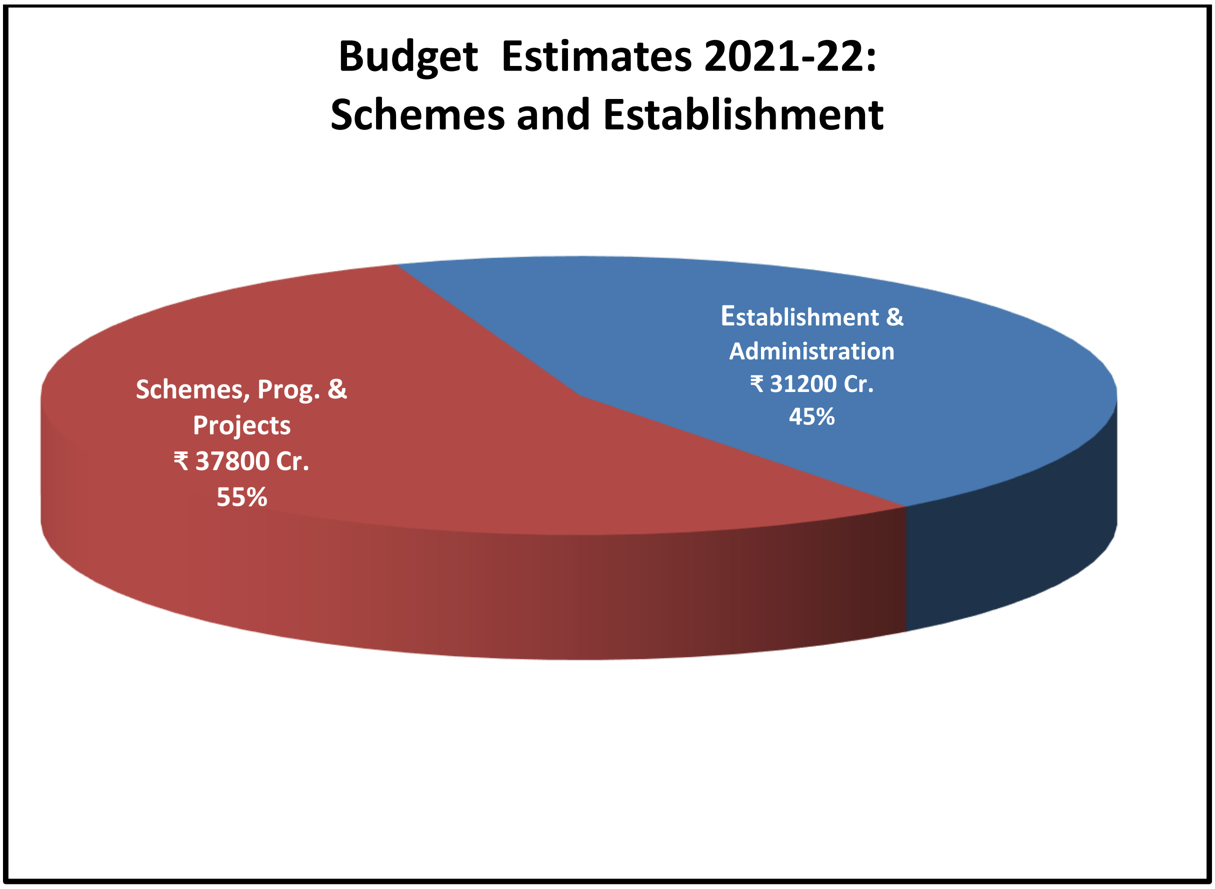
Budget Estimates 2021-22:
Schemes and Establishment
Schemes, Prog. & Projects ₹ 37800 Cr. 55%
Establishment & Administration ₹ 31200 Cr. 45%

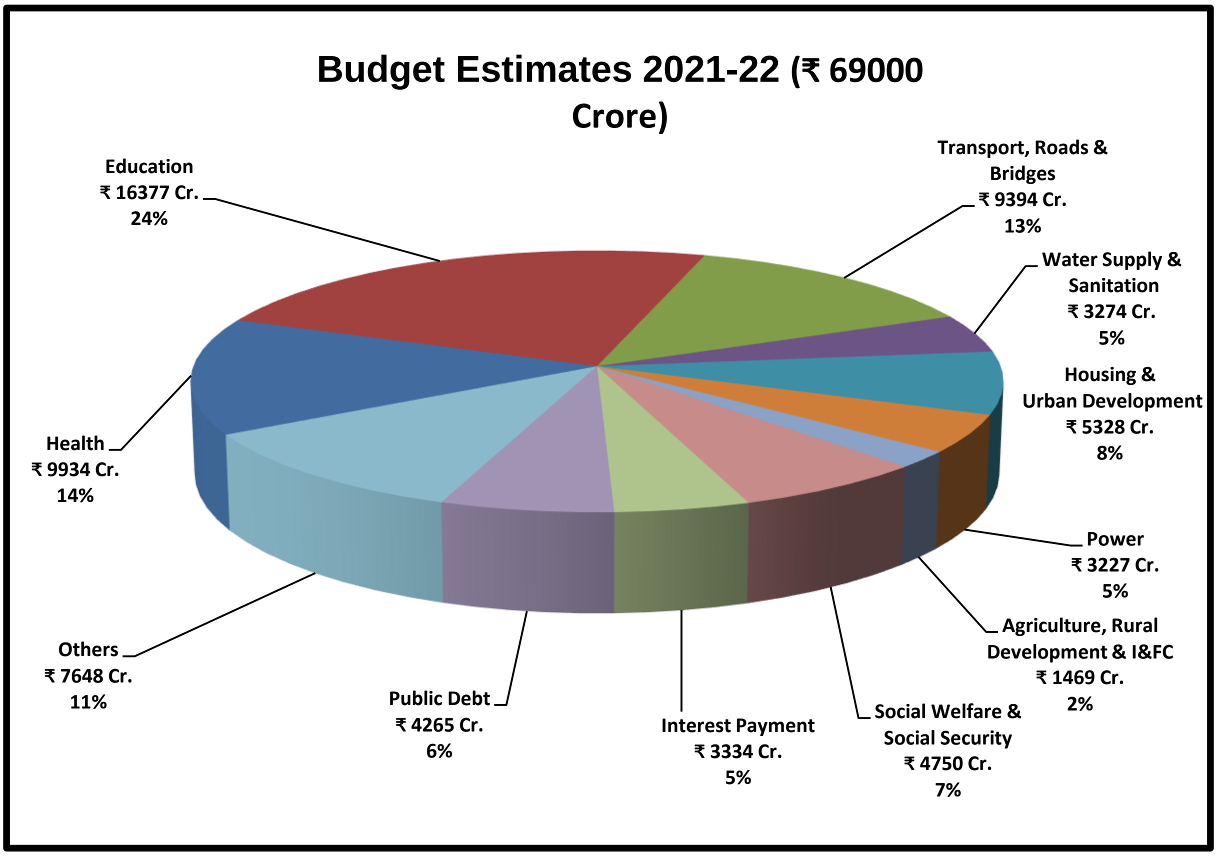
Budget Estimates 2021-22 (₹ 69000 Crore)
Education ₹ 16377 Cr. 24%
Transport, Roads & Bridges ₹ 9394 Cr. 13%
Water Supply & Sanitation ₹ 3274 Cr. 5%
Housing & Urban Development ₹ 5328 Cr. 8%
Health ₹ 9934 Cr. 14%
Power ₹ 3227 Cr. 5%
Agriculture, Rural Development & I&FC ₹ 1469 Cr. 2%
Others ₹ 7648 Cr. 11%
Public Debt ₹ 4265 Cr. 6%
Interest Payment ₹ 3334 Cr. 5%
Social Welfare & Social Security ₹ 4750 Cr. 7%

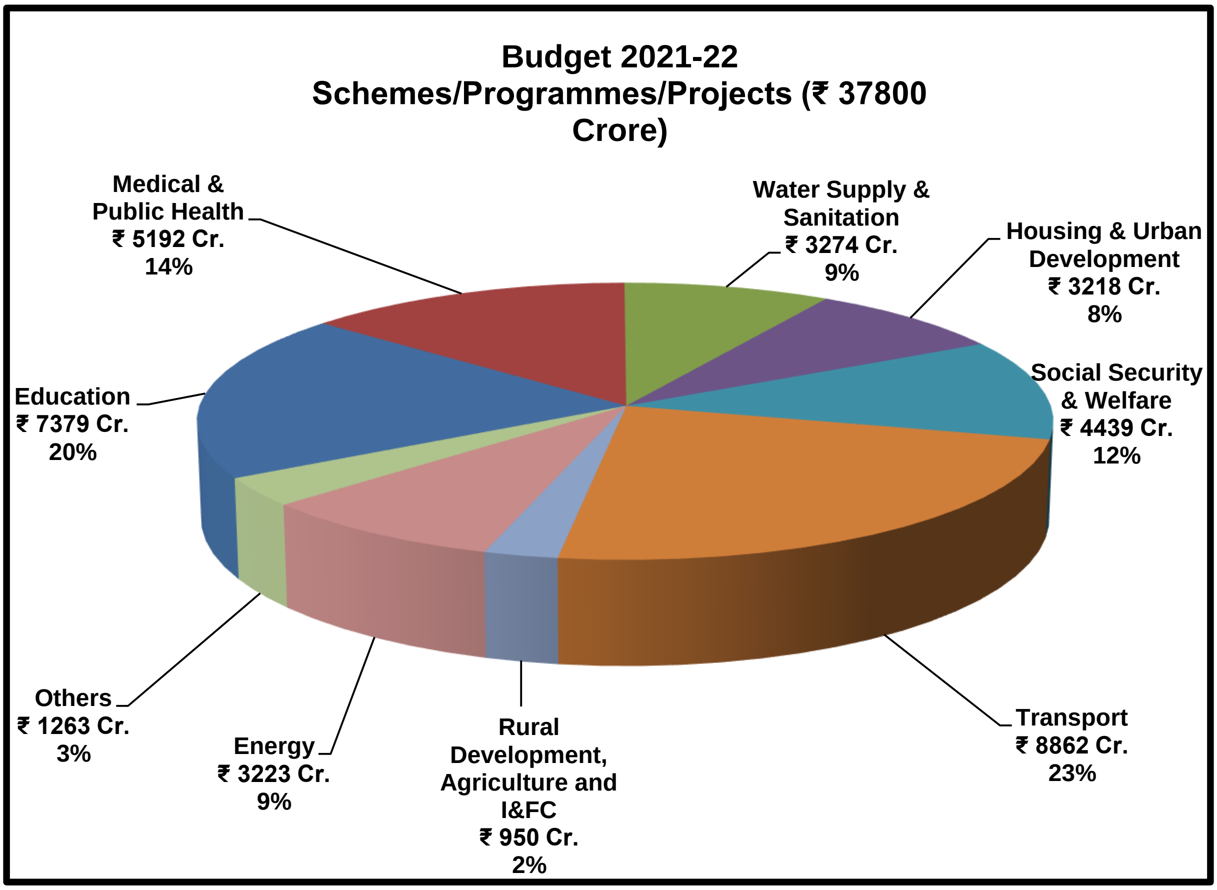
Budget 2021-22 Schemes/Programmes/Projects (₹ 37800 Crore)
Medical & Public Health ₹ 5192 Cr. 14%
Water Supply & Sanitation ₹ 3274 Cr. 9%
Housing & Urban Development ₹ 3218 Cr. 8%
Education ₹ 7379 Cr. 20%
Social Security & Welfare ₹ 4439 Cr. 12%
Others ₹ 1263 Cr. 3%
Energy ₹ 3223 Cr. 9%
Rural Development, Agriculture and I&FC ₹ 950 Cr. 2%
Transport ₹ 8862 Cr. 23%

बजट अनुमान 2021–22

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए रा.रा.क्षेत्र दिल्लीा सरकार का प्रस्तावित बजट रुपये 69,000 करोड़ का है।

योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए बजट	–	रु. 37,800 करोड़
स्थापना बजट	–	रु. 31,200 करोड़
राजस्व मद के अंतर्गत बजट	–	रु. 51,799 करोड़
पूंजी मद के अंतर्गत बजट	–	रु. 17,201 करोड़

❖ **2021–22** के लिए बजट अनुमान रु. **69,000** करोड़, **2020–21** के रु **65,000** करोड़ के बजट अनुमान की तुलना में **6.15** प्रतिशत अधिक है और **2020–21** में रु. **59,000** करोड़ के संशोधित अनुमानों से **16.95** प्रतिशत अधिक हैं।

❖ वर्ष 2021–22 के दौरान 69,000 करोड़ रुपये का बजट मुख्य रूप से स्वयं के संसाधनों से वित्तपोषित किया जाएगा। प्रमुख घटकों में स्वयं कर राजस्व से 43,000 करोड़ रुपये, गैर–कर राजस्व से 1000 करोड़ रुपये, केंद्रीय करों में हिससेदारी से 325 करोड़ रुपये, लघु बचत ऋण से 9,285 करोड़ रुपये, पूंजी प्राप्तियों से 1000 करोड़ रुपये, जीएसटी मुआवजे से 6000 करोड़ रुपये, केंद्र प्रायोजित योजना से 2088 करोड़ रुपये और सहायता अनुदान से मात्र 657 करोड रुपये जुटाए जाएंगे।

दिल्ली की अर्थव्यवस्था

❖ वर्ष 2020–21 के दौरान दिल्ली के जीएसडीपी में (वर्तमान कीमतों पर) 3.92 प्रतिशत और (स्थिर कीमतों पर) 5.68 प्रतिशत का संकुचन हुआ, जिसकी मुख्य् वजह कोविड–19 महामारी से प्राभावित आर्थिक मंदी थी।

❖ वित्तीय वर्ष 2019–20 में स्थिर मूल्यों पर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय यानी रुपये 2,74,671/– देश में दूसरी सबसे ज्यादा औसत आय रही।

❖ वित्तीय वर्ष 2020–21 में वतर्मान मूल्यों पर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय रुपये 3,54,004/– रही जो राष्ट्रीय औसत आय रुपये 1,27,768/– से 2.77 गुणा अधिक है।

❖ रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार का प्रति व्यक्ति व्यय 2015–16 के 19,218/– रुपये से बढकर 2021–22 में रुपये 33,173 होगा।

स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर देशभक्ति बजट

- वित्तीय वर्ष 2021–22 के बजट को स्वतंत्रता संग्राम के महान देशभक्तों और शहीदों की याद में और देश की आजादी के 75 वें वर्ष का उत्सव मनाने के संदर्भ में देशभक्ति बजट के रूप में नामित किया गया है।

- इस अवसर को देखते हुए, दिल्ली शहर "केजरीवाल शासन मॉडल" और पिछले 75 वर्षों में अपनी यात्रा और 2047 में भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अपने विजन को प्रदर्शित करेगा।

- भारत के स्वतंत्रता के **75** वें वर्ष को यादगार बनाने के लिए अनूठे तरीके से कई समारोहों और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम 12 मार्च 2021 से शुरू होंगे, जो शहीद भगत सिंह और बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर के प्रेरणादायक जीवन और भारत की स्वतंत्रता के लिए उनके योगदान, उनके कार्यों तथा देश के लिए उनके सपनों से संबद्ध होंगे।

- सरकार ने देश की पहचान और एकता के प्रतीक शानदार लहराते राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगे के साथ शहर को सजाने की योजना बनाई है, जो शहर भर में 500 स्थानों पर लहराया जायेगा, जिसके लिए बजट में 45 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित है।

- "देश भक्ति पाठयक्रम" सभी सरकारी स्कूलों में लागू किया जाएगा और इसके लिए सभी कक्षाओं में हर रोज एक पीरियड होगा, ताकि विद्यार्थियों के युवा दिमाग में एकता और भाईचारे, देश के लिए प्यार और सम्मान और देशभक्ति और मानवीय मूल्यों के प्रति सम्मान का भाव जगाया जा सके और उन्हें सच्चा नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया जा सके।

- सरकार ने शिक्षा को एक जन आंदोलन बनाने के लिए इस वर्ष से 'यूथ फॉर एजुकेशन' नाम से 'मेंटरशिप वालंटियर' कार्यक्रम प्रस्तावित किया है।

- एनडीए और सैन्या सेवाओं के लिए सरकारी स्कूलों के विद्यर्थियों की सफलतापूर्वक भर्ती के लिए एक नया सैनिक स्कूल और दिल्ली सशस्त्र बल तैयारी अकादमी दिल्ली में स्थापित की जायेगी।

- नागरिकों की मांग पर दिल्ली की विभिन्न कॉलोनियों में ध्यान और योग प्रशिक्षक प्रदान किये जाएंगे, जिसके लिए देशभक्ति बजट में 25 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

- स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष में 'भारत उत्सव' और 'भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह' के तहत भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

- 'मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना' इस दिशा में मील का पत्थर साबित हुई है और इस योजना के तहत 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

स्वास्थ्य

- देश का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में शुरू किया गया था और जरूरतमंद मरीजों को निशुल्क प्लाज्मा उपलब्ध कराना शुरू किया गया। होम आइसोलेशन और प्लाज्मा बैंक की अभिनव व्यवस्था को बाद में न केवल देश में बल्कि दुनिया भर में स्वीकार किया गया और सराहा गया।

- सरकार ने सभी को समान रूप से वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है। प्रारंभिक चरण में लगभग 6 लाख स्वास्थ्य कार्यकर्ता और अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं को शामिल किया गया।

- सरकार ने फैसला किया है कि सरकारी अस्पतालों में कोविड का टीका दिल्ली के लोगों को मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। इस नई योजना – 'आम आदमी मुफ्त कोविड टीका' के लिए 50 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

- दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे में विस्तार के लिए विभिन्न पूंजी परियोजनाओं के लिए 1,293 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। ये परियोजनाएं ज्वालापुर, सिरसपुर, मादीपुर और विकासपुरी में नए अस्पतालों के निर्माण और 19 मौजूदा अस्पतालों को नया रूप देने से संबद्ध हैं।

- बुरारी में 768 बिस्तर के अस्पताल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इसे 450 बिस्तर के साथ कोविड रोगियों के उपचार हेतु खोला गया है। इसी तरह, अंबेडकर नगर अस्पताल भी जुलाई 2020 से कोविड रोगियों के लिए 200 बिस्तर उपलब्ध करा रहा है। द्वारका में निर्माणाधीन इंदिरा गांधी अस्पताल अगले साल से 1,241 बिस्तर की क्षमता के साथ काम करना शुरू कर देगा।

- सरकार ने 'महिला मोहल्ला क्लिनिक' नाम से महिलाओं के लिए एक विशेष मोहल्ला क्लिनिक शुरू करने का प्रस्ताव किया है। वर्ष 2021–22 में, 100 'महिला मोहल्ला क्लीनिक' दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में स्थापित करने का प्रस्ताव है।

- स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष में, दिल्ली सरकार ने दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य कार्ड जारी करने का प्रस्ताव दिया है।

- वर्ष 2021–22 के लिए, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 9,934 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया गया है, जो कुल बजट का 14 प्रतिशत है।

<u>शिक्षा</u>

- ❖ दिल्ली सरकार का शिक्षा मॉडल 'केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस' की नींव है, जिसने शिक्षा पर अपने कुल बजट का एक चौथाई हिस्सा लगातार निवेश करके सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी दी है।

- ❖ शिक्षा क्षेत्र को 2021–22 में रुपये 16,377 करोड़ का बजट आवंटन किया गया है।

- ❖ सरकार ने स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष के अवसर पर देशभक्ति बजट का प्रस्ताव किया है। स्वतंत्र भारत के लिए शहीद भगत सिंह और बाबासाहेब भीम राव अम्बेडकर के प्रेरक जीवन पर और उनके स्वतंत्र भारत के लिए एक रोडमैप बनाने के लिए किये गए संघर्षपूर्ण कार्यों पर कार्यक्रमों के लिए 20 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

- ❖ सरकार ने दिल्ली में एक नया सैनिक स्कूल और दिल्ली सशस्त्र बल प्राथमिक अकादमी शुरू करने का प्रस्ताव दिया है, जहाँ अपने नियमित अध्ययन के साथ–साथ, बच्चों को एनडीए और सेना में भर्ती के लिए भी तैयार किया जाएगा।

- ❖ सरकार ने दिल्ली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन स्थापित करने का प्रस्ताव किया है जो बच्चों को बोर्ड परीक्षा के साथ–साथ हमारे देश के आईआईटी और एम्स जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उनके व्यक्तित्व को समझने की क्षमता विकसित करने में मदद करेगा।

- ❖ IX से XII कक्षा के लिए 100 स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस स्कूल दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में खोले जाएंगे।

- ❖ दिल्ली सरकार ने दिल्ली में स्कूलों की एक नई श्रेणी शुरू करने का फैसला किया है– ' वर्चुअल दिल्ली मॉडल स्कूल' जो "कहीं भी रहना, कभी भी सीखना, कभी भी परीक्षण करना" के सिद्धांत पर शिक्षकों और छात्रों के नियमित शिक्षण, सीखने और बातचीत के लिए एक अनूठा प्रयोग होगा।

- ❖ नई शिक्षा नीति के अनुसार, स्नातक स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण पर ध्यान देने के साथ 4 वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है।

- ❖ युवाओं में अंग्रेजी वार्तालाप कौशल को बेहतर बनाने के लिए, शिक्षा निदेशालय ने स्कूली शिक्षा पूरी करने वाले छात्रों के लिए एक योजना का प्रस्ताव किया है।

- ❖ सरकार ने खेल सुविधाओं को कारगर बनाने और विश्व स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए एक खेल विश्वविद्यालय बनाया है। सरकार का लक्ष्य कम से कम 10 खेल क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता चैंपियन तैयार करना है।

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

❖ अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करने के लिए, सरकार ने एक नई योजना बनाई है–सहेली समंवय केंद्र, जिसके तहत दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में 500 आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

❖ एक अन्य पहल "समृद्धि" आंगनवाड़ी हब मे ंविशेष व्यवस्था के साथ महिलाओं और किशोरियों के सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरण के लिए व्यवस्था की जाएगी और सूक्ष्म–आर्थिक इकाइयो को शुरू करने और स्वयं सहायता समूहों की बैठकें आयोजित करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना है।

❖ सरकार ने महिलाओं को सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करने के लिए 33 स्वयं सहायता इकाइयों की स्थापनाकरने की योजना बनाई है और महिला कल्याण के लिए जी.एन.सी.टी.डी. द्वारा लागू की गई विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने और उन्हें परामर्श देने के लिए उनकी सहायता करने की योजना है।

❖ शहर में मादक पदार्थों और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए, बजट अनुमान 2021–22 में 7.20 करोड़ रुपये की राशि के साथ एक नई योजना 'सूर्योदय' भी पेश की गई है।

❖ अजा/अपिव/अल्पसंख्यक समुदायों के कारीगरों और विकलांगों के लिए दिल्ली हाट की तर्ज पर अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए बाबा साहेब प्रगतिशील विश्वकर्मा शिल्पकार ग्राम योजना प्रस्तावित है। डीएसएफडीसी ने इन कारीगरों के लिए विशेष रूप से शिल्पी हाट का निर्माण करने का प्रस्ताव किया है और दुकानों/थड़ा को उन्हें मासिक पट्टे के आधार पर 05 वर्षों के लिए आवंटित किया जाएगा।

❖ सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के शिक्षण और पुनर्वास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुशल जनशक्ति के विकास के लिए विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव दिया है।

आवास और शहरी विकास

❖ एनडीएमसी, एसडीएमसी और ईडीएमसी की सभी मलिन बस्तियों को श्खुले में शौच मुक्तश घोषित किया गया है। डीयूएसआईबी ने 674 जन सुविधा परिसर वेस्टिर्न सीटों वाले 21,586 शौचालयों बनाए हैं।

❖ 'जहाँ झुग्गी वही मकान' के तहत शानदार आवास प्रदान करने के लिए, डीयूएसआईबी ने स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए" इन–सीटू यानी स्व–स्थाने स्लम पुनर्वास की योजना बनाई है। सुल्तानपुरी में, निकटवर्ती झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को 1,060 घर आवंटित करने का काम अंतिम चरण में है। इसके अलावा देव नगर, करोल बाग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 784 बहुस्तरीय घरों का निर्माण शुरू हो गया है।

पानी की आपूर्ति और स्वच्छता

- पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिए, दिल्ली जल बोर्ड के जल उपचार संयंत्रों में 9 प्रयोगशालाएं 24 घंटे काम कर रही हैं।

- गैर राजस्व पानी को समाहित करने के लिए 3,170 बल्क–फ्लोमीटर पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं और 121 बल्क–फ्लोमीटर स्थापना की प्रक्रिया में हैं।

- अनधिकृत कॉलोनियों में पाइपलाइन जलापूर्ति का नेटवर्क लगातार बढ़ रहा है और वर्तमान में, 93 प्रतिशत परिवार लगभग 14,500 किलोमीटर की पाइपलाइन के नेटवर्क के माध्यम से जलापूर्ति पाते हैं । पाइपलाइन का यह नेटवर्क 1,622 अनधिकृत कॉलोनियों को कवर करता है।

- 'मुख्यमंत्री फ्री सीवर कनेक्शन योजना' के तहत, दिल्ली जल बोर्ड की उन कॉलोनियों में, जहां पिछले वर्षों में सीवर लाइनें बिछाई गई हैं, में दिल्ली जल बोर्ड ने स्वयं की लागत पर 4.88 लाख सीवर कनेक्शन नियमित किए गए थे। यह योजना इस वर्ष भी जारी रहेगी।

- दिल्ली जल बोर्ड ने अपने 771 प्रतिष्ठानों में से 585 में वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित की है और शेष कार्य 2021 मानसून से पहले पूरा होने की उम्मीद है।

- इंटरसेप्टर सीवर परियोजना का काम लगभग पूरा हो गया है। एसटीपी और इंटरसेप्टर की मदद से, यमुना को अब अगले 3 वर्षों में पूरी तरह से साफ किया जा सकता है।

- 20 किलोलीटर मुफ्त पानी सब्सिडी योजना के लिए 600 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया गया है, जिससे हर महीने लगभग 6 लाख लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।

सड़क बुनियादी ढांचा

- कमांड कंट्रोल सेंटर (सीसीसी) सहित लगभग 1,32,000 कैमरे स्थापित किए गए हैं और कार्यात्मक बनाए गए हैं।

- नागरिकों को मुफ्त वाई–फाई देने के लिए 7000 हॉट–स्पॉट की स्थापना का काम पूरा हो गया है और सक्रिय हो गया है।

- आश्रम चौक पर अंडरपास का निर्माण जून 2021 तक पूरा हो जाएगा, जिसके बाद मथुरा रोड (निजामुद्दीन से बदरपुर सीमा) और आश्रम क्रॉसिंग पर यातायात आसान हो जाएगा और यात्रा के समय में कमी, प्रदूषण स्तर और ईंधन की बचत होगी।

- आश्रम फ्लाईओवर का विस्तार डीएनडी फ्लाईओवर के लिए दिसंबर 2021 तक पूरा हो जाएगा। इस फ्लाईओवर और मेट्रो के निर्माण के बाद, नोएडा और लाजपत नगर के साथ–साथ आईटीओ और लाजपत नगर के बीच सड़क उपयोगकर्ताओं को फायदा होगा।

- दो परियोजनाओं का निर्माण– (i) वजीराबाद और आजादपुर के बीच दो अंडरपास और आउटर रिंगरोड पर गांधी विहार के पास एक पैदल यात्री मेट्रो और (ii) बसईदापुर में नजफगढ़ नाले पर एक पुल का निर्माण मई 2021 तक पूरा हो जाएगा।

- सरकार ने पांच नई परियोजनाएँ प्रस्तावित की हैं – पंजाबी बाग फ्लाईओवर और राजा गार्डन के बीच एकीकृत पारगमन गलियारा, ज्वाला हेड़ी मार्केट रेड लाइट से ज्वालापुरी रेड लाइट के बीच एकीकृत पारगमन गलियारा, मुकरबा चौक पर वाहनों की भीड़ कम करने की एक व्यापक योजना, मुख्य बुराड़ी रोड जंक्शन में बुराड़ी समानांतर सड़क पर वाहनों की भीड़ कम करने की योजना, और खेड़ा कलां से खेड़ा खुर्द रोड पर रेलवे क्रॉसिंग नंबर एलसी–12 पर आरओबी/आरयूबी का निर्माण।

परिवहन

- सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए, पहली बार, एक साल के भीतर सोलह सौ बसों का बेड़ा शामिल किया गया है और इस साल सितंबर तक 1,000 और बसें शामिल की जाएंगी। वर्तमान में दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन बेड़े में कुल 6,693 बसें हैं। इस साल 1,000 और बसों को जोड़ने के बाद यह संख्या 7,693 तक पहुंच जाएगी। सरकार ने दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन में 11,000 बस–बेड़े का लक्ष्य रखा है।

- वसंत विहार और हरि नगर में बहुस्तरीय बस डिपो परियोजना नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी (NBCC) के सहयोग से चलायी जा रही है। सरकार 1397 बस क्यू शेल्टर नए डिजाइन के साथ बना रही है।

- अंतिम मील कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 95353 ई–रिक्शा पंजीकृत किए गए हैं। 174 गैर–एसी मेट्रो फीडर बसें परिचालन में हैं, जो यात्रियों के लिए पर्याप्त सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए 32 मार्गों पर चल रही हैं।

- दिल्ली मेट्रो शहर की जीवन रेखा बन गई है और चरण–4 में, 78 नए स्टेशनों के साथ एक और 108 किलोमीटर की दूरी पर है। दिल्ली मेट्रो के चरण– IV के पूरा होने के बाद मेट्रो रेल पर सवारियों के बढ़कर लगभग 71.26 लाख होने की उम्मीद है।

- मयूरविहार पॉकेट–I से त्रिलोकपुरी तक की मेट्रो लाइन मार्च, 2021 में पूरी होने की संभावना है और ढांसा बस स्टैंड के लिए विस्तार कार्य सितंबर, 2021 तक पूरा होना है।

❖ सरकार ने अक्टूबर 2019 से डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की थी और यह 2021–22 में भी जारी रहेगी।

पर्यटन

❖ दिल्ली हेरिटेज प्रमोशन और दिल्ली टूरिज्म सर्किट नामक दो नई योजनाएँ 2021–22 में प्रस्तावित हैं।

❖ पर्यटन स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सभी पर्यटन स्थलों के प्रवेश बिंदुओं पर सीसीटीवी कैमरे लगाना, अंधेरे वाले स्थानों पर एलईडी से रोशनी और DTTDC के सभी पर्यटन स्थलों पर वर्दीधारी गार्डों की नियुक्ति, विभिन्न पर्यटक स्थलों पर मोबाइल वैन की सुविधा जैसे उपाय किए हैं।

पर्यावरण और वन

❖ दिल्ली सरकार ने पर्यावरण के व्यापक संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं, जैसे निर्माण स्थलों पर एंटी–स्मॉग गन का उपयोग, प्रदूषक रोकने के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए जैव–डी–कंपोजर्स के उपयोग को प्रोत्साहित करना जिससे प्रदूषक रोके जा सकें, यांत्रिक रोड स्वीपर की तैनाती, एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट जल उपचार का बेहतर प्रबंधन, खुले में कचरा और पत्तियों को जलाने पर रोक, थर्मल पावर प्लांट बंद करना आदि।

❖ दिल्ली 'इलेक्ट्रिक वाहन राजधानी' बन गई है और सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि 2024 तक, दिल्ली में पंजीकृत होने वाले नए वाहनों में से कम से कम 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन होंगे।

❖ वर्तमान में दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 72 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन कार्यरत हैं और यह संख्या जल्द ही 500 तक पहुंच जाएगी। रैपिड चार्जिंग प्वाइंट भी बनाए जा रहे हैं।

❖ सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में ई–बस को बढ़ावा देने के लिए, सरकार सड़कों पर 1,300 ई–बसें लाने की तैयारी कर रही है। क्लस्टर योजना के तहत अगले साल के मध्य तक 1,000 नई ई–बसें सड़कों पर होंगी।

❖ दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, निर्माण स्थलों पर एंटी–स्मॉग गन स्थापित करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा, दिल्ली में दो स्मॉग टावरों की स्थापना अंतिम चरण में है।

❖ वायु, जल और भूमि प्रदूषण पर निगरानी के लिए एक वास्तविक समय प्रदूषण आकलन प्रणाली आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर के सहयोग से लागू की जा रही है।

- 'देश की पहली' ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी' दिल्ली में लागू की गयी है, जिसके तहत यह अनिवार्य है कि किसी परियोजना के लिए हटाये गए पेडों में से कम से कम 80 प्रतिशत पेड़ अन्य स्थानों पर ट्रांसप्लांट करने होंगे।

- वर्तमान में, दिल्ली में हरित क्षेत्र बढ़कर 21.8 प्रतिशत हो गया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है।

<u>ऊर्जा</u>

- बिजली की खपत में 400 यूनिट तक सब्सिडी की योजना और 1984 के दंगों के पीड़ितों के लिए 100 प्रतिशत सब्सिडी जारी रहेगी।

- सरकार, दिल्ली सौर ऊर्जा नीति के तहत, लोगों/संस्थानों को सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रोत्साहित कर रही है। दिसंबर 2020 तक, दिल्ली में 193 मेगावाट की कुल क्षमता वाली लगभग 4664 सौर ऊर्जा इकाइयाँ स्थापित की गई।

- सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए "मुख्यमंत्री किसान आय बढ़ोतरी योजना" के तहत किसानों द्वारा लगभग 200 एकड़ भूमि दी गई है।

- 11 केवी नेटवर्क के अंतर्गत बेयर कंडक्टर के इंसूलेटिड कंडक्टर में रूपांतर की एक नई योजना (जगमगाती दिल्ली कार्यक्रम के तहत) शुरू की गई है।

''''''